समक्ष माननीय न्यायमूर्ति महेश ग्रोवर

हरजीत कौर और अन्य - याचिकाकर्ता

बनाम

विनोद कुमार और अन्य - प्रतिवादी

2013 की सीआर संख्या **4622**

4 मार्च 2014

*सिविल प्रक्रिया संहिता, **1908** - आदेश **21** नियम **97, 98** और **102** - डिक्री का निष्पादन - वाद की लम्बन के दौरान बिक्री - याचिकाकर्ता डिक्री धारक - मुकदमे के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी द्वारा बेची गई भूमि - कब्जे के वारंट एक रिपोर्ट के साथ बिना निष्पादन के वापस आ गए कि संपत्ति एक कंपनी के नाम पर थी और वारंट निष्पादन के लिए असमर्थ थे - निष्पादन न्यायालय ने आदेश पारित किया कि ख़रीददार व्यक्ति कार्यवाही में पक्षकार नहीं - याचिकाकर्ताओं ने सिविल पुनरीक्षण दायर किया - अभिनिर्धारित, मुकदमे के लम्बन के दौरान की गई बिक्री किसी भी तरह से डिक्री धारक के अधिकारों पर कोई बंधन नहीं लगाएगा - धोखाधड़ी सब कुछ रद्द कर देगी - धोखाधड़ी के कार्य और परिणाम कानून की नजर में शून्य हैं - लागू आदेश को निष्पादन न्यायालय को स्पष्ट निर्देश के साथ रद्द कर दिया गया है डिक्री को तुरंत निष्पादित करने और मुश्तरी कंपनी से कब्जा वापस लेने और याचिकाकर्ताओं को इसे बहाल करने के लिए।*

अभिनिर्धारित , कि मैं याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए विवाद से पूरी तरह सहमत हूं, खासकर तब जब उत्तरदाताओं के पास डिक्री को दी गई अंतिम मंजूरी के मद्देनजर प्रस्ताव देने का कोई औचित्य नहीं है। यदि कोई सीपीसी के आदेश 21 नियम 98 और 102 की भाषा का ईमानदारी से पालन करता है, तो मुकदमे के लंबित रहने के दौरान दर्ज किया गया कोई भी अलगाव किसी भी तरह से मुकदमे की संपत्ति पर कब्जा पाने के लिए डिक्री धारक के अधिकारों पर कोई बाधा नहीं डालेगा। जिसे जाहिरा तौर पर डिक्री धारक के अधिकारों को पराजित करने के लिए बेच दिया गया है। इस मामले में, ऐसे स्पष्ट तथ्य हैं जो दर्शाते हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 से 8 के पूर्ववर्ती द्वारा पूरी तरह से धोखाधड़ी की गई है, जिन्होंने शुरू में नकली मुख्तारनामा बनाया और इसे प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्ववर्ती को बेच

दिया। धोखाधड़ी सब कुछ निष्प्रभावी और ख़राब कर देगी। यह कानून का एक स्थापित प्रस्ताव है कि धोखाधड़ी के कार्य और परिणाम कानून की नजर में अमान्य हैं। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को संपत्ति पर उनके सफल दावे के निष्पादन से दूर रखने का कोई औचित्य नहीं होगा।

(पैरा 6)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिवादी संख्या 2 से 8 के पूर्ववर्ती (कृष्ण लाल) ने स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी की, जिसके कारण याचिकाकर्ताओं को मुकदमेबाजी और पीड़ा का एक लंबा दौर झेलना पड़ा, जो अभी भी कम से कम आदेश पारित होने तक समाप्त नहीं हुआ है। इस अदालत में, उसे बिना किसी परिणाम के छोड़ा नहीं जा सकता। सामान्य तौर पर अदालत ने उसके खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया होगा, लेकिन इस तथ्य के लिए कि वह अब दुनिया में नहीं है, इसलिए, उस पर मौद्रिक परिणाम लागू करना उचित है जो कि 5 लाख रुपये जो 1972 से संपत्ति के अनधिकृत उपयोग और मुकदमेबाजी के खर्चों को कवर करेगा जो याचिकाकर्ताओं को उसके धोखाधड़ी कृत्य के कारण भुगतना पड़ा। लागत कृष्ण लाल की संपत्ति से वसूल की जाएगी और याचिकाकर्ताओं के लिए क्षतिपूर्ति होगी।

केएस बोपाराय, याचिकाकर्ताओं के वकील ।

संजीव गुप्ता, प्रतिवादी नंबर 1 के वकील।

आदिश गुप्ता, प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5 और 8 के वकील।

महेश ग्रोवर**,** माननीय न्यायमूर्ति

C.M. No. 4025-CII of 2014

आवेदन स्वीकार कर लिया गया है और संलग्न दस्तावेज को रिकार्ड में ले लिया गया है।

<u>मुख्य मामला</u>

(1) याचिकाकर्ता डिक्री-धारक हैं जो इसे क्रियान्वित कराना चाहते हैं, लेकिन प्रतिवादियों के कपटपूर्ण कृत्य के कारण उनके प्रयास विफल हो गए हैं,

जिन्होंने शुरू में उनकी भूमि को हड़प लिया और इसे आगे भी बीच दिया ताकि डिक्रीधारक के पक्ष में हुई डिक्री वस्तुतः भ्रामक बन जाये।

(2) याचिकाकर्ताओं ने 15.6.1988 को स्वामित्व के आधार पर कब्जे के लिए एक मुकदमा दायर किया जिसमें वर्तमान उत्तरदाताओं के पूर्ववर्ती कृष्ण लाल और शाम लाल को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था। कृष्ण लाल ने कथित तौर पर फर्जी मुख्तारनामा बनाया और संबंधित जमीन शाम लाल को बेच दी थी। पुनरीक्षण याचिका में वर्तमान प्रतिवादी कृष्ण लाल और शाम लाल दोनों के प्रतिनिधि हैं। विद्वान ट्रायल न्यायालय ने 26.9.1994 को मुकदमा खारिज कर दिया जिसके परिणामस्वरूप अपील दायर की गई जहां अपीलकर्ता यानी याचिकाकर्ता सफल रहे। अपने आदेश दिनांक 21.2.2000 में, अपीलीय अदालत ने मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया, जिसके परिणामस्वरूप 7.2.2007 को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में डिक्री पारित कर दी गई। विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा यह माना गया कि कृष्ण लाल के पक्ष में निष्पादित मुख्तारनामा आम जाली था और इसका तार्किक परिणाम यह था कि कृष्ण लाल ने शाम लाल को भी धोखा दिया था, जिसे जमीन बेची गई थी। कब्जे की डिक्री पारित होने के साथ ही, शाम लाल को धोखाधड़ी वाले लेनदेन के अपराधी यानी कृष्ण लाल के खिलाफ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता भी दी गई। विद्वान ट्रायल कोर्ट के दिनांक 7.2.2007 के इस आदेश के खिलाफ कोई और अपील नहीं की गई, जिसने इसे निष्पादन के उद्देश्य से अंतिम बना दिया।

(3) ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, यह जमीन शाम लाल द्वारा 13.6.1996 को एक गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी के पक्ष में बेच दी गई थी।

(4) निष्पादन में, कब्जे के वारंट जारी किए गए थे, लेकिन राजस्व अधिकारियों ने दिनांक 3.3.2011 की एक रिपोर्ट के साथ वारंट को बिना निष्पादित किए वापस कर दिया कि मुकदमा संपत्ति मैसर्स गोल्डन फारेस्ट इंडिया लिमिटेड के नाम पर थी। गोल्डन फॉरेस्ट (इंडिया) लिमिटेड ने दिनांक 13.6.1996 के विक्रय विलेख के आधार पर कब्जे के वारंट को निष्पादित करने में असमर्थ बना दिया। विद्वान निष्पादन न्यायालय ने दिनांक 24.8.2012 को एक आदेश पारित किया जिसमें उसने पाया कि गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी कार्यवाही में पक्षधर नहीं है और उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ

इंडिया बनाम गोल्डन फॉरेस्ट *(*इंडिया*)* लिमिटेड***, 2003 T.C. (C) No.68 of 2003*** नामक मामले में उचित निर्देश जारी किए गए थे और विभिन्न लेनदारों के दावों की संतुष्टि के लिए एक समिति गठित की गई थी। आज दायर किए गए आवेदन के आधार पर, याचिकाकर्ताओं ने समिति की कार्यवाही को रिकॉर्ड में रखा है, जिसमें उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया है कि "वर्तमान प्रकृति का विवाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश/निर्देश के दायरे में नहीं आता है।" भारत की इस समिति की क्षमता, अधिकार या अधिकार क्षेत्र से संबंधित - जीएफआईएल" और आगे कहा गया कि चूंकि मामला स्वीकार्य रूप से नागरिक प्रकृति का है, इसलिए, यदि सलाह दी जाती है, तो आवेदक सिविल न्यायालय का रुख कर सकते हैं। इसकी पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आदेश 21 नियम 97, 98, 102 सीपीसी के प्रावधानों का उल्लेख किया है और कहा है कि डिक्री धारक होने के नाते, उन्हें कब्जे से वंचित नहीं किया जा सकता है, भले ही संपत्ति को मुक़दमे के लंबित रहने के दौरान बेच दिया गया हो । संदर्भ के उद्देश्य से , आदेश 21 नियम, 97, 98, 102 सीपीसी यहां नीचे दिया गया हैं:--

" **97.** अचल संपत्ति के कब्जे का विरोध या बाधा**.-** (1) जहां अचल संपत्ति के कब्जे के लिए डिक्री धारक या डिक्री के निष्पादन में बेची गई ऐसी किसी संपत्ति के खरीदार का किसी व्यक्ति द्वारा विरोध किया जाता है या प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न की जाती है संपत्ति पर कब्ज़ा होने पर, वह इस तरह के प्रतिरोध या बाधा की शिकायत करते हुए न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

(2) जहां कोई भी आवेदन उप-नियम (1) के तहत किया जाता है, न्यायालय इसमें निहित प्रावधानों के अनुसार आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा।

98. न्यायनिर्णयन के बाद आदेश**.-** (1) नियम 101 में निर्दिष्ट प्रश्नों के निर्धारण पर, न्यायालय, ऐसे निर्धारण के अनुसार और उप-नियम (2) के प्रावधानों के अनुसार,-

(a) आवेदन को अनुमति देने वाला आदेश देगा और निर्देश देगा कि आवेदक को संपत्ति का कब्ज़ा दे दिया जाए या आवेदन खारिज कर दिया जाए; या

(b) ऐसा आदेश पारित करेगा , जो मामले की परिस्थितियों में उचित लगे।

(2) जहां इस तरह के निर्धारण पर, न्यायालय संतुष्ट है कि प्रतिरोध या बाधा बिना किसी उचित कारण के निर्णय-देनदार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके कहने पर या उसकी ओर से, या किसी हस्तांतरिती द्वारा उत्पन्न की गई थी, जहां ऐसा हस्तांतरण किया गया था मुकदमे या निष्पादन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, यह निर्देश देगा कि आवेदक को संपत्ति के कब्जे में रखा जाए, और जहां आवेदक का अभी भी विरोध किया जाता है या कब्जा प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न की जाती है, तो अदालत आवेदक के कहने पर, निर्णय-देनदार, या उसके कहने पर या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को तीस दिन तक की अवधि के लिए सिविल जेल में हिरासत में रखने का आदेश दे सकता है।

xx xx xx

102. नियम लम्बन के दौरान हस्तांतरिती पर लागू नहीं होते हैं । - नियम 98 और 100 में कुछ भी उस व्यक्ति द्वारा अचल संपत्ति के कब्जे के लिए डिक्री के निष्पादन में प्रतिरोध या बाधा पर लागू नहीं होगा, जिसे निर्णय-देनदार ने ऐसे वाद जिसमें डिक्री पारित की गई थी या ऐसे किसी व्यक्ति को बेदखल करने के लिए दायर होने के बाद संपत्ति हस्तांतरित कर दी है।

(5) **उषा सिन्हा बनाम दीना राम और अन्य** [1]में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी निर्भरता की गई है , जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिस पेंडेंस के सिद्धांत के संबंध में कहा है कि कोई तीसरा पक्ष किसी पार्टी से संपत्ति जो मुक़दमे का विषय है खरीदता है , डिक्री धारक के सही दावे का विरोध या बाधा या आपत्ति नहीं कर सकता है। संदर्भ के उद्देश्य से, निर्णय के पैरा 12, 18, 21 से 24 नीचे दिए गए हैं:-

"12. नियम को मात्र पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह न्याय, समानता और अच्छे विवेक पर आधारित है। यह माना जाता है कि किसी निर्णय देनदार से हस्तांतरित व्यक्ति को अदालत के समक्ष होने वाली कार्यवाही के बारे में जानकारी होती है। मुकदमेबाजी का विषय बनी संपत्ति खरीदने से पहले उसे सावधान रहना चाहिए। यह हस्तांतरण अधिनियम,

1882 की धारा 52 द्वारा मान्यता प्राप्त लिस पेंडेंस के सिद्धांत को मान्यता देता है। संहिता के आदेश 21 का नियम 102 इस प्रकार जमीनी हकीकत को ध्यान में रखता है और मुकदमेबाजी के संबंध में संपत्ति के खरीदारों को मदद के लिए हाथ बढ़ाने से इनकार करता है। लंबित है। यदि स्थानांतरित पेंडेंट लाइट को अनुचित, असमान या अवांछनीय सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो डिक्री धारक कभी भी अपने डिक्री के फल का एहसास नहीं कर पाएगा। हर बार जब डिक्री धारक डिक्री को निष्पादित करने के लिए न्यायालय से निर्देश मांगता है, तो निर्णय लेने वाला देनदार या उसका हस्तांतरित व्यक्ति संपत्ति हस्तांतरित कर देगा और नया हस्तांतरित व्यक्ति प्रतिरोध करेगा या बाधा उत्पन्न करेगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए यह नियम बनाया गया है.

xx xx xx

18. इस प्रकार यह स्थापित कानून है कि मुकदमा लंबित होने के दौरान मुकदमे की संपत्ति के खरीदार को सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के निष्पादन का विरोध करने या बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं है। 'लिस पेंडेंस' का सिद्धांत किसी पक्ष को उस संपत्ति से निपटने से रोकता है जो मुकदमे का विषय है। 'लिस पेंडेंस' को क्रेता के लिए कंस्ट्रक्टिव नोटिस के रूप में माना जाता है कि वह लंबित मुकदमे में दर्ज होने वाली डिक्री से बंधा हुआ है।

इसलिए, नियम 102 स्पष्ट करता है कि हस्तांतरित पेंडेंट लाइट द्वारा प्रतिरोध या बाधा नहीं होनी चाहिए। यह घोषणा करता है कि यदि निर्णय देनदार के हस्तांतरित पेंडेंट लाइट द्वारा प्रतिरोध किया जाता है या बाधा उत्पन्न की जाती है, वह आदेश 21 के नियम 98 या 100 का लाभ नहीं मांग सकता। xx xx xx

21. हम सिल्वरलाइन फोरम में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के प्रस्ताव से सम्मानजनक रूप से सहमत हैं। हमारी राय में, यह सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान निर्णय देनदार से संपत्ति खरीदने वाले व्यक्ति को डिक्री के निष्पादन का विरोध करने, बाधा डालने या आपत्ति करने के लिए संपत्ति का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है। कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान किसी निर्णय

देनदार के हस्तांतरण के पर उसके ही अधिकार वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरोध या बाधा नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, वह अपने दावे का न्यायनिर्णयन कराने का हकदार नहीं है।

22. नियम 102 को लागू करने के लिए, डिक्री धारक के लिए यह दिखाना पर्याप्त है कि कब्जे का विरोध करने वाला या बाधा उत्पन्न करने वाला व्यक्ति उस मुकदमे जिसमें डिक्री पारित की गई थी के शुरू होने के बाद संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा कर रहा है और निर्णय देनदार के खिलाफ निष्पादित करने की मांग की गई थी। यदि उक्त शर्त पूरी हो जाती है, तो मामला नियम 102 के अंतर्गत आता है और ऐसा आवेदक आदेश 21 के नियम 98 या नियम 100 पर भरोसा नहीं कर सकता है।

23. जहां तक मौजूदा मामले का सवाल है, तथ्यों पर अब कोई विवाद नहीं रह गया है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, 1999 का टाइटल सूट नंबर 140 उत्तरदाता-वादी द्वारा 10 अप्रैल, 1999 को स्थापित किया गया था। इस प्रकार, संपत्ति के संबंध में मुकदमा लंबित था और मामला विचाराधीन था। इसके बाद अपीलकर्ता ने 15 फरवरी, 2000 को यानी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान एक पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा मूल प्रतिवादी संख्या 4 और 5 से संपत्ति खरीदी। यह भी विवाद में नहीं है कि 24 मई, 2001 को प्रतिवादियों के खिलाफ एकपक्षीय डिक्री पारित की गई थी। इस स्थिति में, हमारी सुविचारित राय में, लिस पेंडेंस का सिद्धांत विचाराधीन लेनदेन पर लागू होगा, और माननीय उच्च न्यायालय यह मानने में पूरी तरह से सही था कि मामला संहिता के आदेश 21 के नियम 102 के अंतर्गत आता है। अपीलकर्ता अपने द्वारा दायर मुकदमे की लंबितता के लिए सुरक्षा की मांग नहीं कर सकती थी। निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन कार्यवाही पर रोक लगाना उचित नहीं था। इसलिए, निष्पादन न्यायालय के आदेश को रद्द करने में उच्च न्यायालय सही था।

24. संहिता के आदेश 21 का नियम 29 उन मामलों से संबंधित है जिनमें निर्णय-देनदार द्वारा डिक्री-धारक के खिलाफ मुकदमा स्थापित किया गया है और लिस पेंडेंस के मामलों से इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, जिसमें संपत्ति का हस्तांतरण निर्णय देनदार द्वारा किसी तीसरे को किया

गया है। उच्च न्यायालय ने, हमारी राय में, सही माना कि अपीलकर्ता को मुकदमे के लिए 'अजनबी' नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह प्रतिवादी नंबर 4 और 5 जिनके खिलाफ मुकदमा लंबित था के माध्यम से अधिकार, शीर्षक और हित का दावा कर रही थी । इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि वह उस मुकदमे से अवगत है जो अपीलकर्ता के पूर्ववर्ती के खिलाफ वर्तमान प्रतिवादी द्वारा दायर 1999 के टाइटल सूट नंबर 140 के रूप में एक सक्षम न्यायालय के समक्ष था। जैसा कि बेलामी मामले में कहा गया है, यह तथ्य कि कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान संपत्ति के खरीदार को मुकदमे, अपील या अन्य कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पूरी तरह से सारहीन है और वह उस आधार पर डिक्री के निष्पादन का विरोध नहीं कर सकता है। जैसा कि सिल्वरलाइन फोरम में देखा गया है, ऐसे मामलों में एक सीमित जांच यह होती है कि क्या हस्तांतरित व्यक्ति निर्णय-देनदार के माध्यम से अपने अधिकार का दावा कर रहा है। हमारे फैसले में, उच्च न्यायालय का यह मानना भी सही था कि यदि अपीलकर्ता मुकदमे में सफल हो जाती है और उसके पक्ष में डिक्री पारित हो जाती है तो वह कानून के अनुसार उचित कार्यवाही कर सकती है और क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकती है। हालाँकि, यह डिक्री धारक को उसके द्वारा प्राप्त डिक्री को क्रियान्वित करने से नहीं रोकता है। चूंकि अपीलकर्ता एक मुश्तरी पेंडेंट लाइट है और उसे प्रतिरोध करने या बाधा उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं है और चूंकि उसके अधिकारों को डिक्री में स्पष्ट नहीं किया गया है, इसलिए संहिता के आदेश 21 का नियम 102 लागू होता है। इसलिए, वह अपने द्वारा दायर मुकदमे के लंबित रहने के दौरान निष्पादन का विरोध नहीं कर सकती। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अवैध, गैरकानूनी या अन्यथा कानून के विपरीत नहीं कहा जा सकता है।

(6) मैं याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क से पूरी तरह सहमत हूं, खासकर तब जब उत्तरदाताओं के पास डिक्री को दी गई अंतिम मंजूरी के मद्देनजर प्रस्ताव देने का कोई औचित्य नहीं है। यदि कोई ईमानदारी से आदेश 21 नियम 98 और 102 सीपीसी

की भाषा का पालन करता है, तो मुकदमे के लंबित रहने के दौरान दर्ज किया गया कोई भी हस्तांतरण किसी भी तरह से मुकदमे की संपत्ति पर कब्जा पाने के लिए डिक्री धारक के अधिकारों पर कोई बाधा नहीं डालेगा। डिक्री धारक के अधिकारों को पराजित करने के लिए स्पष्ट रूप से हस्तांतरित कर दिया गया है। इस मामले में, ऐसे स्पष्ट तथ्य हैं जो दर्शाते हैं कि उत्तरदाताओं संख्या 2 से 8 के पूर्ववर्ती द्वारा पूरी तरह से धोखाधड़ी की गई है, जिन्होंने शुरू में जाली मुख्तारनामा बनाया और इसे प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्ववर्ती को बेच दिया। धोखाधड़ी सब कुछ निष्प्रभावी और ख़राब कर देगी। यह कानून का एक स्थापित प्रस्ताव है कि धोखाधड़ी के कार्य और परिणाम कानून की नजर में अमान्य हैं। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को संपत्ति पर उनके सफल दावे के निष्पादन से दूर रखने का कोई औचित्य नहीं होगा।

(7) इसलिए, याचिका स्वीकार कर ली गई है और लागू आदेश को तुरंत डिक्री निष्पादित करने और मेसर्स गोल्डन फ़ॉरेस्ट (इंडिया) लिमिटेड से कब्ज़ा वापस पाने के लिए निष्पादन न्यायालय को इस स्पष्ट निर्देश के साथ खारिज कर दिया गया है की वे इसे याचिकाकर्ताओं को बहाल करें क्योंकि कोई भी अन्य विकल्प केवल उस कार्य को कायम रखेगा जिसका उद्देश्य धोखाधड़ी और उसके बाद के हस्तांतरण यानी मैसर्स गोल्डन फ़ॉरेस्ट किसी डिक्री के निष्पादन में बाधा नहीं डाल सकता। वे वास्तव में कानून का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(8) आदेश देने से पहले, मैं इस तथ्य पर टिप्पणी नहीं कर सकता कि उत्तरदाताओं संख्या 2 से 8 के पूर्ववर्ती कृष्ण लाल ने स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी की, जिसके कारण याचिकाकर्ताओं को मुकदमेबाजी और पीड़ा के लंबे दौर में जाना पड़ा, जो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। कम से कम इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित होने तक उसे बिना किसी परिणाम के छोड़ा नहीं जा सकता। सामान्य तौर पर यह अदालत उसके खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दे देती, लेकिन इस तथ्य के कारण कि वह अब दुनिया में नहीं है, उसे आर्थिक दंड देना उचित लगता है, जो कि 5 लाख रुपये निर्धारित किया जाता है, जो

1972 से संपत्ति के अनधिकृत उपयोग और मुकदमेबाजी का खर्च जो याचिकाकर्ताओं को उसके कपटपूर्ण कृत्य के कारण भुगतना पड़ा को कवर करेगा । लागत कृष्ण लाल की संपत्ति से वसूल की जाएगी और याचिकाकर्ताओं की क्षतिपूर्ति होगी। निष्पादन न्यायालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि आदेश की एक प्रति और इस न्यायालय को भेजी गई रिपोर्ट की प्राप्ति के दो महीने के भीतर निष्पादन किया जाए। निष्पादन में बाधा डालने के किसी भी प्रयास को इस न्यायालय द्वारा अवज्ञा के कार्य के रूप में देखा जाएगा और अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। याचिकाकर्ता ऐसी स्थिति में इस न्यायालय को उचित रूप से अवगत कराने के लिए स्वतंत्र होंगे।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

उदित अग्रवाल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा